



## भारत और चीन : वैश्वीकरण के विविध आयाम

प्रदीप मौर्य

### ABSTRACT :

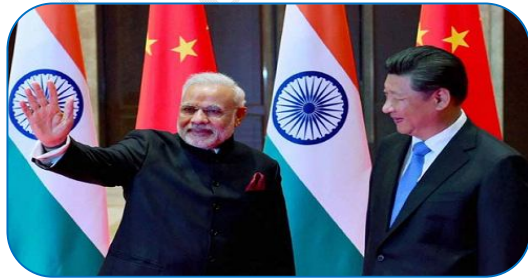
भारत और चीन दोनो विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ थी प्राचीन काल से ही दोनो देशों के मध्यसांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक सम्बन्धों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है वर्तमान वैश्विक-परिदृश्य में विश्व राजनीति का रूप रंग बदल रहा है लेकिन बौद्ध धर्म की जो परम्परा भारत वर्ष ने शुरू की वह भारत के रास्ते चीन तक पहुँची। चीन के माध्यम से वह कोरिया व जापान तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। दोनों ही देश लगभग एक ही समय में स्वतन्त्रता प्राप्त की थी तथा साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का दंश इन देशों ने सहा है। लेकिन 21वीं सदी के प्रथम व द्वितीय दशको में चीन एवं भारत ने विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, चीन विश्व का 'विनिर्माण हब' बनता जा रहा है, तो वही भारत विश्व का मुख्य 'सेवा प्रदाता' की भूमिका में विश्व मानचित्र पर रेखांकित है।

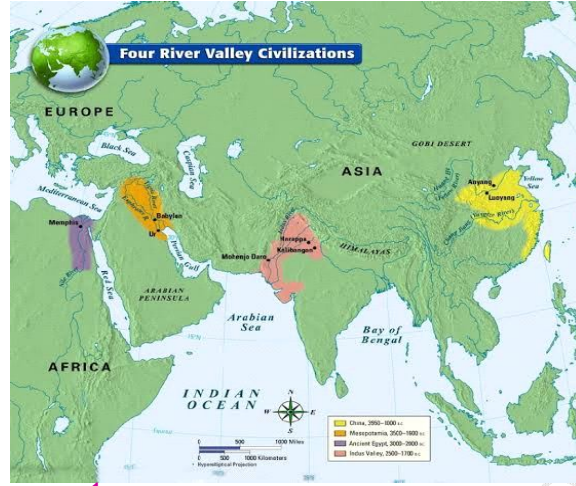
वैश्वीकरण के इस युग में चीन व भारत एशिया की ही नहीं अपितु विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्तियाँ है। प्रस्तुत आलेख में इसी विषय पर विश्लेषण किया गया है।

### प्रस्तावना –

भारत व चीन, दोनो ही विश्व के विस्तृत भू-भाग व विशाल जनसंख्या वाले देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन ने अपनी विस्तारवादी एवं अवसरवादी विदेश नीति को प्रमुखता दी तो वही भारत ने पंचशील के सिद्धान्तों पर चलकर अपनी विदेश नीति को धार दिया। 1913-1914 के दौरान खींची गयी मैकमोहन रेखा दोनों देशों के मध्य सीमा की सुरक्षा से एक महत्वपूर्ण कदम था लेकिन चीन द्वारा इसको नकारने से अन्ततः 1962 में भारत-चीन युद्ध ने दोनो देशों के सम्बन्धों में खटास पैदा कर दी।

वर्तमान समय, सीमा-विवाद, जल विवाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की बात हो या आतंकवाद एवं जलवायु परिवर्तन की हो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। आर्थिक महाशक्ति की होड़ ने भारतीय बाजारों को चीनी उत्पादों से भर दिया, अर्थात् कभी मुद्रा का अवमूल्यन तो कभी 'एन्टी डम्पिंग कर' अनेक हथकंडों से महाशक्ति का सम्बन्ध विच्छेद की पुनरावृत्ति बढी है। मई 2014 में भारत को प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व प्राप्त हुआ है। वैश्वीकरण के दौर ने चीन को एशिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है, 'OBOR परियोजना' हो या 'स्ट्रिंग ऑफ पर्स' (String of Pearls) की नीति हो चीन के इस अभियान ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नये अध्याय को मान्यता दी है। चीनी राष्ट्रपति 'शी जिनपिंग' तथा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हाल ही में सम्पन्न 'शंघाई सहयोग संगठन' (SCO) के बैठक के दौरान दोनो राष्ट्रों के बीच सहयोगात्मक सम्बन्धों को नई दिशा प्रदान करने की वार्ता हुयी है, जो अन्ततः वैश्विक पटल पर इनकी प्रभावकारी क्षमता को दर्शाता है।





### चीनी आर्थिक सुधार नीति (1978)<sup>1</sup> –

चीन ने आर्थिक सुधार नीति को छह (6) स्तरों पर बाँटा है।

1. पहले स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार था, जिसके तहत कृषि क्षेत्र में पुनर्संरचना को मजबूत करना था। धीरे-धीरे कृषि क्षेत्र ने अपने व्यापक परिवर्तन से चीन को कृषि प्रधान देश के रूप में आत्मनिर्भर बना दिया।<sup>2</sup>
2. द्वितीय स्तर पर **“Open-door”** नीति के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की स्थापना करना था। परिणाम स्वरूप Shenzhen, Zhuhai, Shantou और Xiamen को 1980 तक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से खोल दिया गया। फलतः यांग्तीज (yangtze) नदी के किनारे स्थित शहर विश्व व्यापार के केन्द्र बन गये।
3. तीसरे स्तर पर चीन ने **‘स्वामित्व संरचना’ (Ownership structure)** में सुधार किया तथा एक मिश्रित आर्थिक पद्धति को प्रमुखता दी जिसके तहत स्वामित्व में **‘प्राइवेट सेक्टर’** की भागीदारी सुनिश्चित की।<sup>3</sup>
4. चतुर्थ स्तर के सुधार के रूप में चीन ने **‘मूल्य पद्धति’ (Price system)** में की पूर्व स्थिति में मुद्रा के प्रवाह पर सरकार का नियन्त्रण था जिसको परिवर्तित कर **‘द्वि-स्तरीय मूल्य पद्धति’ (Double-track pricing system)** लागू की गयी अर्थात् अब वस्तु और सेवा को बाजार एवं सरकार दोनों के माध्यम से विनियमित किया जायेगा।<sup>4</sup>
5. पाँचवें स्तर का **‘आर्थिक सुधार 1979’** में शुरू हुआ जिसने चीनी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया इस स्तर को **‘वित्तीय सुधार’ (Financial Reform)** नाम दिया गया, जिसके तहत **‘पीपुल बैंक ऑफ चाइना’** के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना को अनुमति प्रदान की गयी। जिसका प्रभाव विदेशी मुद्रा विनियम के रूप में सामने आया।
6. अन्त में चीनी आर्थिक सुधार ने सबसे बड़ा सुधार किया जिसको नाम दिया गया **‘कर सुधार’ (Reform of taxation)** इसके तहत प्राचीन पद्धति को बदल दिया गया, पहले सिर्फ केन्द्र सरकार ही कर को लगाती एवं इकट्ठा करती थी वही नई व्यवस्था के तहत केन्द्रीय व स्थानीय प्रभुत्व दोनों को कर के अधिकार प्रदान किये गये परिणाम स्वरूप चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार बढ़ता गया जिससे तटीय एवं स्थलीय भागों में कर अन्तराल में कमी आयी।

चीन ने अपनी आर्थिक नीति में सुधार के लिए उठाये गये कदमों पर चलते हुए, विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है।<sup>6</sup>



### भारतीय आर्थिक सुधार नीति –

भारतीय अर्थव्यवस्था 1980 के दशक तक एक बन्द अर्थव्यवस्था थी, तत्पश्चात् 1990 के दशक में शुरू हुई *'New Economic Policy'* (नई आर्थिक सुधार नीति) जो 1991 में भारतीय प्रधानमंत्री पी0वी0 नरसिम्हा राव एवं वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के विचारों की उपज थी। परिणाम स्वरूप भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया आज के परिदृश्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह भारत की तरफ हो रहा है, जिसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के *'Make in India'* अभियान की परिणिति है।

### नरेन्द्र मोदी : भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में स्थापित करने की पहल –

16 मई 2014 को नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री पद पर आरूढ हुए जो स्वतंत्रता के बाद (1947) पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे।

नरेन्द्र मोदी आर0एस0एस0 (RSS) के विचारों से प्रभावित है। जो *'हिन्दुत्व'* व *हिन्दू राष्ट्र* को मान्यता देता है।<sup>5</sup>

2014 के वर्षों के बाद से वैश्वीकरण की पहल को मजबूती प्रदान करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया जिसके तहत आर्थिक विकास, सुशासन (Smart Governance) जिसकी परिणिति *“न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन (Minimum Government, Maximum Governance)”* के रूप में हुयी।

1991 की निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति को नई दिशा प्रदान करते हुए नई सरकार ने बैंकिंग, सेवा, विनिर्माण, रक्षा आदि क्षेत्रों में भारत को महाशक्ति बनाने का प्रयास किया है।

वैश्वीकरण की बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत को एशिया की नेतृत्व क्षमता के प्रदर्शन को मजबूत किया है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे— *UNO, IMF, BRICS, WTO, SCO, ASEAN* आदि संगठनों में भारत ने अपनी दावेदारी को मजबूती से स्थापित किया है।

### निष्कर्ष :-

वैश्वीकरण का दौर परमाणु युग का है। भारत और चीन दोनों ही परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हैं, दोनों ही देश प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन से सम्पन्न हैं जो विश्व शक्ति के रूप में इनको स्थापित करती है, आजादी के समय से लेकर वर्तमान समय तक भारत व चीन के रिश्तों में उतार-चढ़ाव परिलक्षित होते हैं, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पहलू है। दोनों राष्ट्रों के मध्य बहुत लम्बी सीमा रेखा है जो भू-राजनीतिक महत्व को दर्शाती है,

अन्ततः हम कह सकते हैं कि *“21वीं सदी एशिया की सदी है, जो चीन व भारत रुपी रथ के पहिए पर टिकी है”*।

**सन्दर्भ सूची –**

1. Sheying chen, "*Economic Reform and Social Change in China : past, present and future of the Economic state,*" International Journal of politics, culture and society 15, No. 4 (2002); 569-589.
2. Richard pomfret, "*chinese Economic Reform, 1978-1994,*" Most : Economic policy in Transitional Economics 5, No. 1 (1995) : 13-27.
3. xiao-yuan Dong and Louis putterman, "*China's state-owed Enterprises in the first Reform Decade : An Analysis of a Declining monopsony,*" Economics of planning 35, No. 2 (2002) : 109-139.
4. Guy S. Liu and Gaia Garnio, "*China's Two Decades of Economic Reform,*" Economic of Planning 34, No. 1-2 (2001) : 1-4
5. The Editorials, "*of Dharma and Artha ;,*" *Economic and political weekly* 49, No. 22 (May 31, 2014). Retrieved on may 29, 2014 from [http://www.epw.in/editorials/dharma and artha.html](http://www.epw.in/editorials/dharma%20and%20artha.html).